GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS WORLD PCS
Committed To Excellence
ISO 9001 Certified

1 - 15 Nov., 2018

PIB PICTURE

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

सुरक्षित नगर परियोजना

(PIB, 01 Nov.)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

हाल ही में गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष योजना के अंतर्गत लखनऊ के लिए 194.44 करोड़ रुपये की सुरक्षित नगर परियोजना को मंजूरी दी है।

यह परियोजना केंद्र प्रायोजित होगी और इसमें 60:40 अनुपात में केंद्र और राज्य राशि लगाएंगे।

यह स्वीकृति 8 चयनित शहरों- मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा लखनऊ में सुरक्षित नगर परियोजनाओं को लागू करने की योजना के भाग के रूप में दी गई है।

उद्देश्य

इसका उद्देश्य निर्भया कोष के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संबंधित शहरों की महापालिकाओं तथा पुलिस आयुक्तों और सिविल सोसायटी संगठनों के परामर्श से लागू की जा रही है।

लखनऊ के लिए सुरक्षित नगर परियोजना को उत्तर प्रदेश पुलिस लागू करेगी और महापालिका और शहर परिवहन प्राधिकरण द्वारा इसमें सहायता दी जाएगी। लखनऊ में सुरक्षित नगर परियोजना के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण घटक हैं :

एकीकृत स्मार्ट नियंत्रण कक्ष की स्थापना

- महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए पिंक आउट-पोस्ट(चौकियों) (पूर्णत: महिला पुलिस द्वारा संचालित) की स्थापना
- महिला पुलिस का पिंक पेट्रोल(गश्त)
- परामर्शदाताओं के साथ सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना
- वर्तमान आशा ज्योति केंद्र को सुदृढ़ बनाना
- कैमरा सहित बसों में सुरक्षा उपायों को लागू करना
- अप्रिय घटना की संभावना वाले क्षेत्रों की प्रकाश व्यवस्था में सुधार
- पिंक शौचालयों की स्थापना
- एकल एमर्जेन्सी नम्बर के साथ महिला शक्ति- हेल्पलाइन का एकीकरण

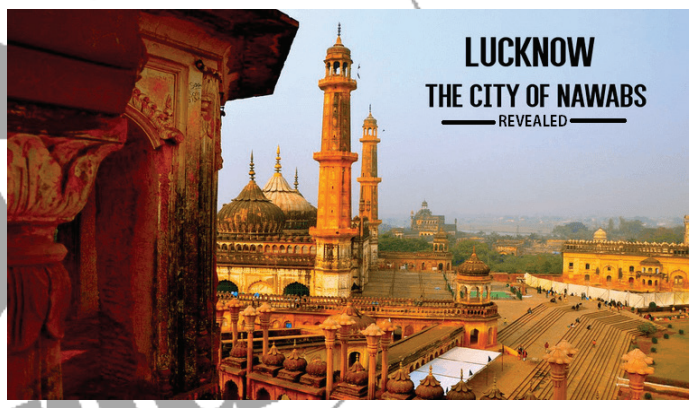

लखनऊ के लिए सुरक्षित नगर परियोजना में लैंगिक समानता के बारे में प्रचार-प्रसार समुदाय और सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग से करने का प्रावधान है।

समर्थन और आउटरीच पहल

(PIB, 02 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
संबंधित मंत्री- श्री गिरिराज सिंह (राज्यमंत्री, स्वंतत्र प्रभार)

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के लिए सरकार के समर्थन और आउटरीच पहल के लॉन्चिंग समारोह में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और समर्थन के लिए 12 महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की।

इन 12 पहलों से इस क्षेत्र के विकास के 5 पहलुओं को संबोधित करने में मदद मिलेगी, जिसमें क्रेडिट तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है।

निम्नानुसार 12 पहल हैं

- एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक आसान पहुंच और 1 करोड़ रुपये तक ऋण प्रदान करने के लिए 59 मिनट के ऋण पोर्टल का शुभारंभ हुआ।
- ताजा या वृद्धिशील ऋण पर, सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट। इसमें निर्यातकों के लिए ब्याज छूट में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की वृद्धि शामिल होगी।
- 500 करोड़ रूपये के कारोबार वाली कंपनियों को व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर लाई जाएंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एमएसएमई से कुल खरीद के 20 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से खरीददारी करेंगी।
- एमएसएमई से 25 प्रतिशत खरीद अनिवार्य है, जिसमें 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित होना चाहिए।

- केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य रूप से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का हिस्सा होना चाहिए।
- देश भर में 20 प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाए जाएंगे और उपकरण कक्षों के रूप में 100 प्रवक्ता स्थापित किए जाएंगे।
- फार्मा कंपनी क्लस्टर की स्थापना की 70 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- इंस्पेक्टर द्वारा देखी जाने वाली प्रतिष्ठानों को कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से तय किया जाएगा।
- वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत, एक उद्यमी को अब विलयित पर्यावरणीय निकासी और सहमति प्राप्त होगी।

- उसको खुद 100 जिलों में एमएसएमई के काम की समीक्षा करनी होगी।
- कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए, उद्यमी को अब न्यायालयों से संपर्क नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सही कर सकते हैं।
- इस आउटरीच कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी अगले 100 दिनों में की जाएगी।
- उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का भी प्रस्ताव रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास जन धन खाते, भविष्य निधि और बीमा है।

ऑपरेशन ग्रीन के लिए मार्ग-निर्देश जारी

(PIB, 05 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
संबंधित मंत्री- श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

संदर्भ

हाल ही में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने टमाटर, आलू तथा प्याज के लिए "ऑपरेशन ग्रीन्स" को मंजूरी दे दी है।

इस ऑपरेशन के तहत टमाटर, प्याज तथा आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा।

मुख्य बिंदु

लघुकालीन कीमत स्थिरता उपाय

- कीमत स्थिरता उपाय के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि कोआपरेटिव मार्केटिंग संघ (NAFED) नोडल एजेंसी होगी।
- केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा टमाटर, प्याज और आलू की फसल के स्टोरेज फैसिलिटी तक परिवहन के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी।

दीर्घकालीन एकीकृत वैल्यू चैन विकास परियोजना

- FPO का क्षमता निर्माण
- गुणवत्ता युक्त उत्पादन
- खेत से फसल निकलने के बाद प्रसंस्करण सुविधा
- कृषि लोजिस्टिक्स
- मार्केटिंग
- फसलों की मांग व आपूर्ति के लिए ई-प्लेटफार्म की व्यवस्था

इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम 50 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को ग्रांट-इन-ऐड के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके तहत राज्य कृषि तथा अन्य मार्केटिंग संघ, कोआपरेटिव, कंपनियां, किसान उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करण, लोजिस्टिक्स ऑपरेटर, सप्लाई चैन ऑपरेटर इत्यादि को सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या है?

"ऑपरेशन ग्रीन्स" की घोषणा 2018-19 के बजट में की गयी थी, इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इस ऑपरेशन के तहत खेत से फसल निकालने के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हैं, इसके लिए स्टोरेज सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

इससे इन फसलों की कीमत अस्थिरता में भी कमी आयेगी।

इससे किसानों को भी उनकी फसल के लिए उचित कीमत मिलेगी, इससे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में सहायता मिलेगी।

मुख्य उद्देश्य

- उत्पादकों तथा ग्राहकों के लिए कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना।
- फसल की कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सुविधा तथा लोजिस्टिक्स सुविधा कम होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना।
- टमाटर, आलू और प्याज की मांग व आपूर्ति के सम्बन्ध में डाटा एकत्रीकरण के लिए मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना करना।

MOFPI
Ministry of Food Processing Industries
Government of India

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food
FSSAI License and Registration System

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

(PIB, Times of India, 05 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री- श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के अंतर्गत असम, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए 113 करोड़ रु. की धनराशि निर्गत की है।

मुख्य बिंदु

2018-19 की अवधि में गृह मंत्रालय अब तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों को 637.98 करोड़ रुपये का आवंटन दे चुका है। 2017-18 में 1,100 करोड़ रु. दिए गये थे।

BADP के अंदर आने वाले राज्य

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

प्रमुख उद्देश्य

BADP का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की विकास से सम्बंधित आवश्यकताओं और उनको पूरा करना और उनके कल्याण के लिए काम करना है।

इस योजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का लाभ पहुँचाना और उसके लिए आवश्यक निर्माण कार्य करना है।

BADP के लिए राशि की व्यवस्था

BADP के लिए 100% राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाती है। यह राशि व्ययगत नहीं होती।

BADP द्वारा संचालित योजनाएँ हैं- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना, पाठशालाओं का निर्माण करना, पेयजल की आपूर्ति करना, सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना, सम्पर्क बढ़ाना, जल-निकास की व्यवस्था करना आदि-आदि।

जो अन्य योजनाएँ BADP के अन्दर आती हैं, वे हैं- स्वच्छता अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन, ग्रामीण और सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा, धरोहर स्थलों की सुरक्षा, दूरस्थ और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हैलीपेडों का निर्माण।

भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह

(PIB, 12 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- शिपिंग मंत्रालय
संबंधित मंत्री- नितिन गडकरी

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2018 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2400 करोड़ रुपये की सौगात दी।

श्री मोदी ने रामनगर स्थित पहले वॉटर वेज टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आदि मौजूद थे।

यह जलमार्ग वाराणसी-हल्दिया मार्ग पर बनाया गया है।

प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में देश के पहले मल्टी-मॉडल टर्मिनल समेत 2413 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया।

वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग

गंगा नदी में बंगाल से वाराणसी तक पोत का परिचालन शुरू हो गया है। आजाद भारत में पहली बार गंगा के रास्ते एक कंटेनर कोलकाता से वाराणसी पहुंचा है।

पेप्सिको कंपनी गंगा नदी के रास्ते जलपोत एमवी आरएन टैगोर के जरिए अपने 16 कंटेनर को कोलकाता से वाराणसी लेकर आई।

इनलैंड वाटर हाइवे-1 पर दो जहाजों के माध्यम से ये कंटेनर आए, जिन्हें 30 अक्टूबर को कोलकाता से रवाना किया गया था।

यह जलपोत एमवी आरएन टैगोर वाराणसी से इफ्को कंपनी का उर्वरक लेकर वापस कोलकाता लौटेंगे।

इस टर्मिनल को हल्दिया-वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकसित किया जा रहा है।

इस टर्मिनल के जरिए 1500 से 2000 टन के बड़े जहाजों की भी आवाजाही संभव हो सकेगी।

भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग

- **राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (इलाहाबाद से हल्दिया):** गंगा नदी से गुजरनेवाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का दर्जा दिया गया है।
- गंगा नदी का प्रयोग नागरिक यातायात तथा भारवहन के लिए काफी समय से किया जाता रहा है।
- इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (सादिया से धुबरी पट्टी):** ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सदिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के नाम से जाना जाता है।
- इस जलमार्ग को वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इस जलमार्ग की कुल लम्बाई 891 किमी है इस राजमार्ग के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र धुबरी, गोगीघोपा, गुवाहाटी, तेजपुर, निमाती, डिब्रूगढ, सदिया तथा सायखोवा है।

- **राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (कोल्लम से कोट्टापुरम):** पश्चिमी भारत में स्थित तटीय नहरों की श्रृंखला को कोट्टापुरम से कोल्लयम तक राष्ट्रीय जालमार्ग - 3 घोषित किया गया है।
- इस जलमार्ग की शुरूआत वर्ष 1992 में हुई थी। इस राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 205 किमी है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (काकीनाडा से मरक्कानम):** काकीनाडा पुदुचेरी नहर विस्तार के साथ गोदावरी नदी विस्तार तथा कृष्णा नदी विस्तार को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग-4 नाम से जाना जाता है।
- इस जलमार्ग की लंबाई 1095 किमी है। यह जलमार्ग चेन्नई बंदरगाह को काकीनाडा तथा मच्छलीपट्टम के बन्दरगाहों को जोड़ता है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (तलचर से धमरा):** पूर्वी तटीय नहर प्रणाली में ब्राह्मणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के नाम से जाना जाता है।
- यह जलमार्ग मंगलगड़ी से पारादीप बन्दरगाह के बीच 101 किमी जलमार्ग को भी जोड़ता है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 623 किमी है।
- इसकी शुरूआत 1985 में हुई थी। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग-6 (लखीपुर से भंगा):** भंगा से लखीपुर जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहा गया है। अभी यह जलमार्ग प्रस्तावित है इसकी शुरूआत अभी नहीं हुई है।
- इस राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 121 किमी है।

30 वर्ष बाद दो तोपों को शामिल किया गया

(PIB, 09 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री- निर्मला सीतारमण

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय सेना में 09 नवम्बर, 2018 को दो तोपों को शामिल किया गया है।
- 30 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय सेना में किसी तोप को शामिल किया गया है।
- इनमें एक अमेरिकन तोप है तो दूसरी कोरियन तोप है।
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देवलाली में एम 777 ए2 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर और के 9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन को सेना को सौंपा।
- बोफोर्स के बाद ये पहली 155 एमएम तोप है जो कि भारतीय सेना में शामिल हुई है। इससे आर्टिलरी की ताकत में इजाफा होगा।

विशेषता

- एम-777 ए2 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर की मारक क्षमता 31 किलोमीटर है।
- महज 30 सेकेंड में ये तीन राउंड फायर कर सकता है।
- इसे हेलिकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए हाई ऑल्टिट्यूड एरिया में भी तैनात की जा सकती है।
- सेना के लिए कुल 145 एम 777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर खरीदे गए हैं।
- ये हल्के तोप चीन से लगी सीमा पर तैनात किये जाएंगे।
- वहीं के-9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन रेगिस्तान के लिए सबसे बढ़िया गन है।
- हूबहू टैंक की तरह दिखने वाली इस तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है।
- 15 सेकेंड में ये तीन राउंड फायर करेगी। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये सड़क हो या रेगिस्तान दोनों जगह पर समान स्पीड 60 किलोमीटर प्रतिघंटे से ज्यादा रफ्तार से दौड़ सकती है।
- भारतीय सेना को ऐसी 100 गन मिलेंगी।

- मेक इन इंडिया के तहत दक्षिण कोरिया की कंपनी भारत की एलएंडटी के साथ 90 तोप बनाएगी, बाकी 10 सीधे दक्षिण कोरिया से आएंगी।

टिप्पणी

- के-9 वज्र के प्रोजेक्ट पर 4,366 करोड़ रुपए और एम-777 हॉवित्जर के प्रोजेक्ट पर 5070 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।
- यह काम नवंबर 2020 तक पूरा होगा। सेना को के-9 श्रेणी की 100 तोपें सौंपी जानी है। इस महीने 10 तोपें सौंपी जाएंगी।
- अगली 40 तोपें नवंबर 2019 में और बाकी 50 तोपें नवंबर 2020 तक सौंपी जाएंगी।
- सौ से अधिक 'एम-777' तोपों की खरीद के लिए भारत ने नवंबर, 2016 में अमेरिका से 5,070 करोड़ रुपए की लागत का एक अनुबंध किया था।
- विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत यह अनुबंध किया गया था।

SIMBEX 2018: भारत और सिंगापुर

(PIB, 09 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री- निर्मला सीतारमण

संदर्भ

हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच SIMBEX (Singapore-India Maritime Bilateral Eñercise) युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है।

यह इस अभ्यास का 25वां संस्करण है। इस अभ्यास का आयोजन 10 से 21 नवम्बर, 2018 के दौरान किया जा रहा है।

इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कई चरणों में अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। यह 1994 के बाद का सबसे बड़ा SIMBEX अभ्यास है।

क्या है?

- इस अभ्यास में कई प्रकार की गतिविधियाँ की जाएँगी, इसमें मिसाइल फायरिंग, हैवी वेट टारपीडो, मध्यम दूरी की तोप, पनडुब्बी रोधी राकेट फायरिंग, एडवांस्ड एंटी-सबमरीन वारफेयर अभ्यास, पनडुब्बी बचाव कार्य, एकीकृत थल तथा हवाई युद्ध अभ्यास, UAV ऑपरेशन तथा क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर उड़ान इत्यादि शामिल हैं।
- इस अभ्यास के शुरुआती चरण का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया जायेगा, इसके बाद अगले चरण का आयोजन अंडमान सागर में किया जायेगा।
- इस अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जायेगा। इस अभ्यास के अंतिम चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जायेगा।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना द्वारा मिसाइल और टारपीडो फायरिंग का सर्वाधिक उपयोग किया जायेगा, इतनी मात्रा में टारपीडो व मिसाइल फायरिंग का उपयोग भारतीय नौसेना ने किसी विदेशी नौसेना के साथ आज तक नहीं किया है।
- भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास में रणवीर श्रेणी के विध्वंसक पोत आईएनएस रणविजय, दो प्रोजेक्ट 17 बहुभूमिका वाली स्टेल्थ फ्रिगेट (आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सह्याद्री), प्रोजेक्ट 28 ASW कार्वेट (आईएनएस कदमत्त), प्रोजेक्ट 25A मिसाइल कार्वेट शामिल है।

- इसके अलावा, आईएनएस कर्च, OPV सुमेधा और आईएनएस सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप, आईएनएस शक्ति, सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बी, आईएनएस सिन्धुकिरती, P8I लम्बी दूरी का गश्ती जहाज, INAS 312, डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती एयरक्रॉफ्ट, UH3H, सीकिंग 42B, सीकिंग 42C तथा चेतक हेलीकॉप्टर इत्यादि हिस्सा ले रहे हैं।
- इस अभ्यास में सिंगापुर नौसेना की ओर से दो फोरमिडेबल श्रेणी की स्टेल्थ फ्रिगेट RSS फॉरमिडेबल व RSS स्टेडफास्ट, दो मिसाइल कार्वेट-RSS विगौर व RSS वेलियंट, एक लिटोरल मिशन वेसल-RSS यूनिटी, आर्चर श्रेणी पनडुब्बी, RSS स्वोड्समैन, स्विफ्ट रेस्क्यू नामक समुद्री बचाव वेसल, फोक्कर F50 समुद्री एयरक्रॉफ्ट, S70B हेलीकॉप्टर तथा स्कैन ईगल नामक मानव रहित विमान हिस्सा ले रहे हैं।

वैश्विक शीतकरण नवाचार शिखर सम्मेलन

(PIB, 10 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री- श्री हर्षवर्धन

संदर्भ

हाल ही में नई दिल्ली में द्वि-दिवसीय वैश्विक शीतकरण नवाचार शिखर सम्मेलन (Global Cooling Innovation Summit) आयोजित होने जा रहा है।

यह शिखर सम्मेलन क्या है?

इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा रॉकी माउंटेन इंस्टिट्यूट, अलायन्स फॉर एन एनर्जी एफीसिएंट इकॉनमी (AEEE), कंजर्वेशन X लैब्स और CEPT यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है।

इस शिखर सम्मेलन में कमरों में लगाए जाने वाले वातानुकूलन मशीनों की बढ़ती माँग से उत्पन्न जलवायविक खतरे के समाधान के लिए ठोस उपायों पर चर्चा होगी।

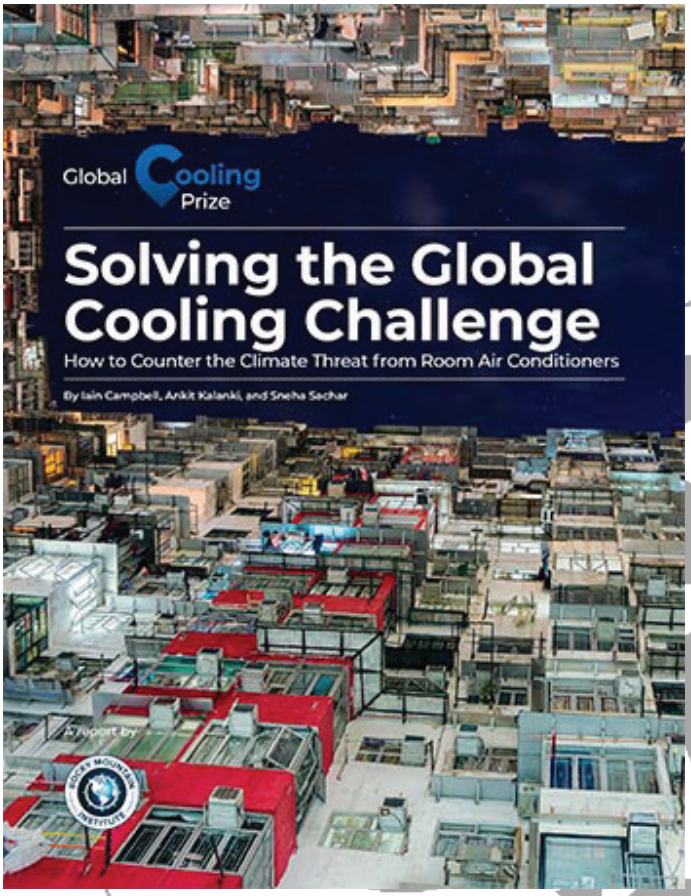

ग्लोबल कूलिंग प्राइज

इस सम्मेलन में ग्लोबल कूलिंग प्राइज नामक पुरस्कार का अनावरण होगा।

यह पुरस्कार उसे दिया जाएगा जो आवासों में ऐसे वातानुकूलन मशीनों का आविष्कार करेंगे, जो आजकल की ऐसी मशीनों की तुलना में जलवायु पर कम-से-कम 5 गुना कम दुष्प्रभाव डालते हों।

महत्त्व

इस पुरस्कार से विश्व का ध्यान आवासीय वाताकूलन से होने वाले दुष्प्रभाव की ओर जाएगा तथा इसके समाधान के लिए नए-नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस पुरस्कार से अनुसंधानकर्ताओं को इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नवाचार की ओर प्रवृत्त हों।

जीसैट-29 का सफल प्रक्षेपण

(PIB, 14 Nov.)

संबंधित मंत्रालय- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री- श्री हर्षवर्धन

संदर्भ

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 14 नवंबर, 2018 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह जीसैट-29 का सफल प्रक्षेपण किया।

इस उपग्रह का वजन 3,423 किलोग्राम है तथा यह उपग्रह इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-एमके3-डी2 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया।

यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ 67वां और भारत का 33वां संचार सैटेलाइट है।

क्या होगा लाभ?

- इसरो द्वारा प्रक्षेपित किये गये जीसैट-29 उपग्रह को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
- इससे जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी।
- उपग्रह में यूनिक किस्म का हाई रिजॉल्यूशन कैमरा लगा है।
- इसे जियो आई नाम दिया गया है। इससे हिंद महासागर में जहाजों पर भी निगरानी की जा सकेगी।
- यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपग्रह की मदद से

भविष्य के स्पेस मिशन के लिए पहली बार इन तकनीकियों का परीक्षण किया गया है।

जीएसएलवी-एमके3-डी2 रॉकेट

जीसैट-29 को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी-एमके 2-डी2 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है।

इसे भारत का सबसे वजनी रॉकेट माना जाता है, जिसका वजन 640 टन है।

इस रॉकेट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह भारत में बना है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 15 साल लगे हैं।

इस रॉकेट की ऊंचाई 13 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर है और ये चार टन तक के उपग्रह लॉन्च कर सकता है।

अपनी पहली उड़ान में इस रॉकेट ने 3136 किलोग्राम के सेटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाया था।

इस रॉकेट में स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ नया क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है।

GSLV MK3-D2 की दूसरी उड़ान होगी, जो लॉन्च होने के बाद 10 साल तक काम करेगा।

लॉन्च होने के बाद इसे पृथ्वी से 36,000 किमी दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट (जीएसओ) में स्थापित किया गया है।

भारत के संचार उपग्रह

दूरसंचार के प्रयोजनों के लिए संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है।

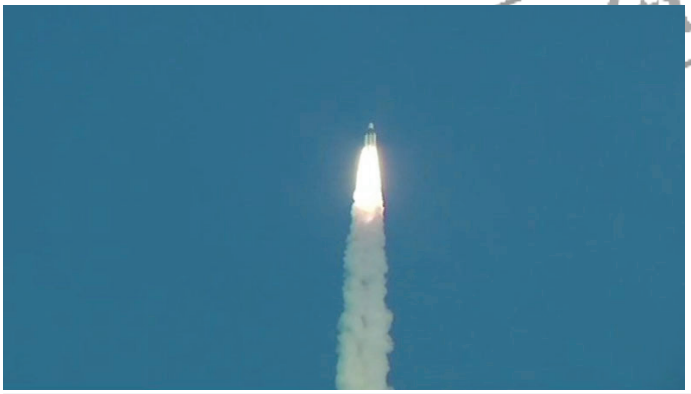

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली, भूस्थिर कक्षा में स्थापित नौ प्रचलनात्मक संचार उपग्रहों सहित एशिया-पेसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रहों में से एक है।

इन्सैट-1बी से शुरूआत करते हुए इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति की शुरूआत की तथा बाद में भी इसे बरकरार रखा।

वर्तमान में प्रचलनात्मक संचार उपग्रह है इन्सैट-3ए, इन्सैट-3सी, इन्सैट-3ई, इन्सैट-4ए, इन्सैट-4सी.आर, जीसैट-8, जीसैट-10 तथा जीसैट-12 ।

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद्

(PIB, 15 Nov.)

संबंधित आयोग - नीति आयोग

संबंधित अध्यक्ष - नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत

संदर्भ

हाल ही में भारत के हिमालय क्षेत्र में सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने एक क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया है जिसको हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद् (Himalayan State Regional Council) का नाम दिया गया है।

परिषद् के बारे में

स्वरूप : हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद् के अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत होंगे।

इसके अन्य सदस्य होंगे- हिमालयी राज्यों के मुख्य सचिव, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के सचिव और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी।

इनके अतिरिक्त इस परिषद् में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

उद्देश्य : इस परिषद् का उद्देश्य 5 कार्यदलों के प्रतिवेदनों के आधार पर चुने गये कार्यों की समीक्षा और कार्यान्वयन होगा।

परिषद् की कार्यसूची के लिए पाँच थीमों से सम्बंधित कार्यावली निर्धारित करने के लिए कार्यदलों का गठन किया गया था।

कार्य

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद् हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के लिए नाभिक एजेंसी होगी।

हिमालयी क्षेत्र में 12 राज्य और 4 जिले आते हैं। ये राज्य एवं जिले हैं- जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिले (दीमा और हसाओ), कार्बी आंगलोंग तथा पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग और कलिमपोंग।

भूमिका

हिमालय क्षेत्र के अनोखेपन को देखते हुए वहाँ के सतत विकास के लिए जून 2, 2017 में नीति आयोग ने पाँच कार्यदलों का गठन किया था।

अगस्त, 2018 में नीति आयोग ने इन पाँच कार्यदलों के थीम पर आधारित प्रतिवेदनों को निर्गत किया था तथा इन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्यावली का निर्धारण किया था।

इसके लिए जिन पाँच थीमों का चयन किया गया था, वे हैं-

- जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमालय के जलस्रोतों का सूचीकरण और उनका कायाकल्प।
- भारत के हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन।
- कृषि पद्धति का रूपांतरण।
- हिमालय क्षेत्र में कौशल और अध्यवसाय के परिदृश्य।
- समुचित निर्णय के लिए डाटा एवं सूचनाओं का संग्रहण।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'सुरक्षित नगर परियोजना' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   1. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र सरकार की सौ प्रतिशत भागीदारी है।
   2. यह योजना कुछ चयनित शहरों में लागू की जायेगी जिसमें लखनऊ भी शामिल हैं।
   3. इसका उद्देश्य निर्भया कोष के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा को मजबूत बनाना।

   नीचे दिए गये कूट के सही प्रयोग से सही उत्तर चुनिए:
   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) केवल 3
   (d) 1, 2 और 3

2. हाल ही में चर्चित 'समर्थन और आउटरीच पहल' के सम्बन्ध में क्या सत्य नहीं है?
   (a) इस पहल का सम्बन्ध सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के विकास से है।
   (b) इसके अंतर्गत बारह पहले शामिल है।
   (c) इसके अंतर्गत प्रारम्भ की गयी पहल में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के लिये क्रेडिट तक आसान पहुंच शामिल है।
   (d) इस योजना का सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है।

3. निम्नलिखित में से 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश से केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली द्वारा चलायी गयी योजना है।
   2. इसका सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है जिसमें टमाटर, आलू तथा प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

4. 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस कार्यक्रम में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए राज्य शामिल हैं।
2. इस कार्यक्रम में सौ प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

5. हाल ही में गंगा नदी में निम्नलिखित में से किसके मध्य पोत परिचालन प्रारंभ किया गया है?
(a) प्रयागराज से वाराणसी के मध्य
(b) वाराणसी से बंगाल तक
(c) वाराणसी से सादिया तक
(d) प्रयागराज से हल्दिया तक

6. हाल ही में भारतीय सेना में शामिल एन 777ए2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह स्वदेश निर्मित है जिसे हेलिकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट विमान के माध्यम से ऊँचाई वाले स्थानों पर भी तैनात की जा सकती है।
2. इस तोप का एक प्रतिरूप के-9 तोप है जिसे अमेरिका से आयात किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

7. हाल ही में समाचारों में चर्चित 'सिम्बेक्स-2018' के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
(a) यह भारत-सिंगापुर के मध्य सम्पन्न युद्ध अभ्यास है।
(b) इसका आयोजन अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में किया गया था।
(c) इसमें मिसाइल फायरिंग, हैवीवेट टारपीडो तथा क्रास डेक हेलीकॉप्टर उड़ान जैसे गतिविधियाँ शामिल थीं।
(d) उपर्युक्त सभी

8. 'वैश्विक शीतकरण नवाचार शिखर सम्मेलन' के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?
1. यह एक संयुक्त शिखर सम्मेलन है जिसके आयोजकों में भारत भी शामिल है।
2. इस सम्मेलन में ग्लोबल कूलिंग प्राइज का शुभारंभ किया गया है।
3. इस शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से वातानुकूलित मशीनों की मांग से होने वाले जलवायुविक खतरों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गयी।
नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

9. जीसैट-29 उपग्रह के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक संचार उपग्रह है जो इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है।
2. इस उपग्रह का प्रक्षेपण जीएसएलवी-MK-3-D2 स्वदेशी रॉकेट से किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

10. हाल ही में चर्चित 'हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद' का गठन निम्नलिखित में से किसने किया है?
(a) नीति आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) रक्षा विभाग
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं